चार्ट III.20: पांच सबसे बड़े बैंकों का सीआरएआर

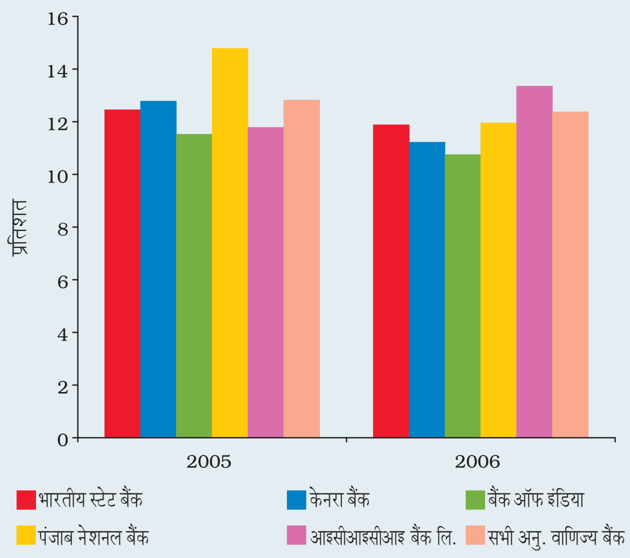

जोखिम भारों में वृद्धि और बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) कोटि के निवेशों के लिए बाजार जोखिम पर पूँजी प्रभार लगाए जाने के कारण, कम हो गया।

3.84 पाँच सबसे बड़े बैंकों ,जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल आस्तियों के 40.7 प्रतिशत थे, के सीआरएआर ने भिन्न - भिन्न प्रकार की प्रवृत्ति दिखाई। आइसीआइसीआइ बैंक को छोड़कर, सभी बैंकों के सीआरएआर में वर्ष के दौरान गिरावट आई (चार्ट III.20)।

3.85 वैयक्तिक बैंक स्तर पर, पुराने निजी क्षेत्र के समूह में दो बैंकों (सांगली बैंक लि. और यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक)[5] को छोड़कर सभी बैंकों का सीआरएआर नौ प्रतिशत की न्यूनतम पूँजी आवश्यकता से ऊपर था। 78 बैंकों का सीआरएआर 10 प्रतिशत से ऊपर था (सारणी III.38 और परिशिष्ट सारणी III.30)। इस स्तर पर, वाणिज्यिक बैंक कुल मिलाकर बासेल II के पूंजी पर्याप्तता के मानकों को पूरा कर सकेंगे।

6. पूँजी बाजार में बैंकों का परिचालन

3.86 31 मार्च 2007 से बासेल II की अपेक्षाओं और ऋण की अधिक मांग को पूरा करने के लिए अनेक वाणिज्यिक बैंकों ने 2005-06 के दौरान पूँजी बाजार में प्रवेश किया।

प्राथमिक पूँजी बाजार से बैंकों द्वारा संग्रहीत संसाधन

3.87 सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने अपने पूँजी आधार को मजबूत करने के लिए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पूँजी बाजारों से संसाधनों की बड़ी राशि जुटाई। 2005-06 के दौरान, घरेलू पूँजी बाजार से सार्वजनिक निर्गमों के माध्यम से बैंकों का कुल संसाधन संग्रहण 24.0 प्रतिशत बढ़ा। द्वितीयक बाजार में बैंकिंग क्षेत्र के शेयरों की कीमतों की स्थिर प्रवृत्ति और मुख्यत: बेहतर ऋण परिवेश के कारण संतोषजनक वित्तीय परिणामों से प्रेरित होकर ग्यारह बैंकों ने 2005-06 के दौरान इक्विटी बाजार से 11,067 करोड़ रुपए जुटाए। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा जारी छह इक्विटी निर्गमों की कुल राशि 5,413 करोड़ रुपए तथा निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा जारी पाँच इक्विटी निर्गमों की कुल राशि 5,654 करोड़ रुपए (प्रीमियम सहित) शामिल थी (सारणी III.39)।

सारणी III.38: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की जोखिम भारित आस्तियों के प्रति पूँजी का अनुपातवार वितरण

(बैंकों की संख्या)

बैंक समूह	2004-05				2005-06			
	4 प्रतिशत से न्यून	4-9 प्रतिशत के बीच	9-10 प्रतिशत के बीच	10 प्रतिशत से अधिक	4 प्रतिशत से न्यून	4-9 प्रतिशत के बीच	9-10 प्रतिशत के बीच	10 प्रतिशत से अधिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
राष्ट्रीकृत बैंक	–	–	2	17	–	–	–	19
स्टेट बैंक समूह	–	–	–	8	–	–	–	8
अन्य सरकारी क्षेत्र के बैंक	–	–	–	1	–	–	–	1
पुराने निजी क्षेत्र के बैक	1	1	3	15	2	–	1	16
निजी क्षेत्र के नए बैंक	–	–	2	7		–	1	7
विदेशी बैंक	–	–	1	30	–	–	2	27
कुल	**1**	**1**	**8**	**78**	**2**	**–**	**4**	**78**

– : नहीं / नगण्य।

[5] चूंकि यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक का सीआरएआर नकारात्मक हो गया अत: बैंक को अधिस्थगन के अंतर्गत रख दिया गया और बाद में आइडीबीआइ लि. के साथ विलय कर दिया गया (ब्यौरा बॉक्स III.1 में)।

सारणी III.39: बैंकिंग क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक निर्गम

(राशि करोड़ रुपए)

वर्ष	सरकारी क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के बैंक		कुल		सकल जोड़
	इक्विटी	ऋण	इक्विटी	ऋण	इक्विटी	ऋण	
1	2	3	4	5	6	7	**8**
2003-04	1,104	–	–	1,352	1,104	1,352	**2,456**
2004-05	3,336	–	4,108	1,478	7,444	1,478	**8,922**
2005-06	5,413	–	5,654	–	11,067	–	**11,067**

– : कुछ नहीं / नगण्य

3.88 पूँजी बाजार में प्रवेश करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के छह बैंक थे : इलाहाबाद बैंक, ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स, सिंडीकेट बैंक, आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (सारणी III.40)। वर्ष के दौरान पूंजी बाजार से संसाधन जुटाने वाले निजी क्षेत्र के पाँच बैंक थे : लक्ष्मी विलास बैंक लि., यस बैंक लि., आइसीआइसीआइ बैंक लि., द साउथ इंडियन बैंक लि. और द यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि.।

3.89 किसी भी बैंक ने सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से ऋण नहीं उगाहे।बैंकों द्वारा 2005-06 के दौरान प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए उगाहे गए संसाधनों में भी 98.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई (सारणी III.41)।

सारणी III.40: बैंकों द्वारा सरकारी निर्गम के जरिए जुटाए गए संसाधन – 2005-06

बैंक का नाम	अंकित मूल्य (रुपए)	निर्गम मूल्य (रुपए)	निर्गम आकार (करोड़ रुपए)		
			राशि	प्रीमियम	कुल
1	2	3	4	5	6
इलाहाबाद बैंक	10	82	100	720	820
ओरिएंटल बैंक	10	250	58	1,392	1,450
सिंडीकेट बैंक	10	50	50	200	250
आंध्र बैंक	10	90	85	680	765
बैंक ऑफ बड़ौदा	10	230	71	1,562	1,633
युनियन बैंक ऑफ इंडिया	10	110	45	450	495
क. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक					**5,413**
लक्ष्मी विलास बैंक	10	50	9	36	45
यस बैंक	10	45	70	245	315
आइसीआइसीआइ बैंक	10	525	98	5,003	5,101
दि साउथ इंडियन बैंक	10	66	23	127	150
दि युनाइटेड वेस्टर्न बैंक	10	24	18	25	43
ख. निजी क्षेत्र के बैंक					**5,654**
कुल (क + ख)					**11,067**

द्वितीयक बाजार में बैंकिंग शेयरों का प्रदर्शन

3.90 पिछले दस वर्षों की प्रवृत्ति को जारी रखते हुए, मजबूत विदेशी संस्थागत निवेशकों के अंतर्वाहों के कारण, 2005-06 के दौरान भारत के शेयर बाजार में उछाल की स्थितियां दिखी, जो मुख्य रूप से सुदृढ़ समष्टि आर्थिक मूलभूत तत्वों और कंपनी लाभप्रदता में सुधार से प्रेरित थीं। 10 मई 2006 को बीएसई संवेदी सूचकांक अब तक के सर्वाधिक उच्च स्तर 12612.38 पर बंद हुआ। लेकिन, इसके तुरंत पश्चात, घरेलू शेयर बाजार में बड़े अंतरराष्ट्रीय इक्विटी बाजारों, विशेष रूप से उभरते बाजारों के अनुरूप तीव्र सुधार दिखा जो मुख्य रूप से लंदन मेटल एक्सचेंज (एलएमई) में मूलभूत धातु के मूल्यों में तीव्र कमी और अमरीकी ब्याज दरों में और वृद्धि की आशंकाओं के कारण था। भारतीय इक्विटी बाजार में विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारी निवल बिक्री, वैश्विक कच्चे तेल के वैश्विक मूल्यों में तीव्र वृद्धि की चिंताओं और बड़ी मुद्राओं की तुलना में रुपये के मूल्य में ह्रास ने भी बाजार के उत्साह को कम किया। 14 जून 2006 को बीएसई संवेदी सूचकांक 8,929 पर पहुँचा जिसमें मार्च 2006 के अंत से 20.8 प्रतिशत की गिरावट दिखी। तथापि, शेयर बाजार ने हानियों की भरपाई की क्योंकि 3 नवंबर 2006 को बीएसई संवेदी सूचकांक 13,131 की नई ऊचाइयों पर पहुँच गया, जिससे विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा नई बिक्री, सुदृढ़ समष्टि आर्थिक मूलभूत तत्वों, अच्छे कंपनी निष्पादन और बड़े-बड़े अंतरराष्ट्रीय शेयर बाजारों में सुधार का पता चलता है।

सारणी III.41: बैंकों द्वारा निजी प्लेसमेंट के जरिए जुटाए गए संसाधन

(राशि करोड़ रुपए)

श्रेणी	2004-05		2005-06	
	निर्गमों की संख्या	जुटाई गई राशि	निर्गमों की संख्या	जुटाई गई राशि
1	2	3	4	5
निजी क्षेत्र के बैंक	44	6,180	24	7,834
सरकारी क्षेत्र क्षेत्र के बैंक	43	9,039	73	22,317
कुल	**87**	**15,219**	**97**	**30,151**

चार्ट III.21: बैंक स्टाकों और शेयर बाजारों में उतार-चढ़ाव

चार्ट III.21(क): बीएसई सेंसेक्स और बैंकेक्स में उतार-चढ़ाव
(मार्च 2004 को सामान्यीकृत = 100 तक)

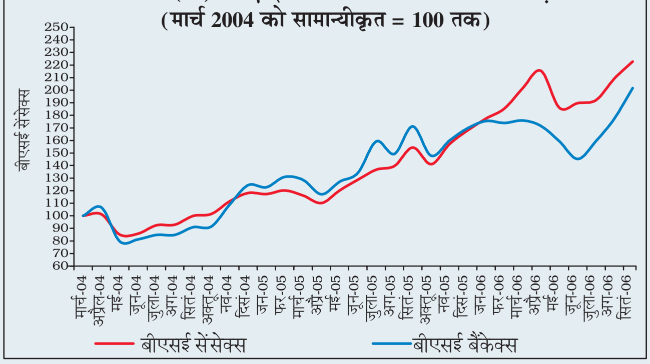

चार्ट III.21(ख): एस एंड पी सीएनएक्स निफ्टी और निफ्टी बैंक इंडेक्स
(मार्च 2004 को सामान्यीकृत = 100 तक)

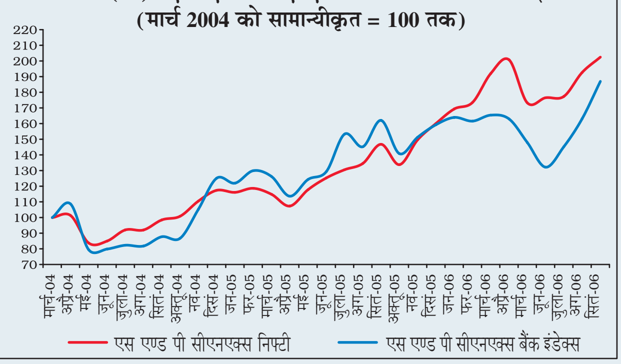

3.91 सामान्य सुधार की प्रवृत्ति के अनुरूप, बैंकिंग क्षेत्र के शेयर, दिसंबर 2005 तक स्थिर बने रहे [चार्ट III.21 क और 21(ख)]। अनुकूल समष्टि आर्थिक मूल-सिद्धांतों के अलावा, बैंकों के शेयर कुछ विशिष्ट क्षेत्र की गतिविधियों से प्रभावित थे। बैंक के तुलनपत्र में सुधार तथा बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों में प्रगति का परिणाम यह हुआ कि बैंकों के शेयरों में लोगों की रुचि बढ़ गई। बैंकिंग क्षेत्र के शेयरों में अन्य अनेक कारकों के कारण मुनाफा हुआ, जैसे स्थायी बांड और अन्य हाइब्रिड लिखत जारी करने के लिए बैंकों को अनुमति देना , बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित अनुकूल प्रस्तावों को 2006-07 के संघीय बजट में शामिल करना, जैसे-अविक्रेय विशेष प्रतिभूतियों का भारत सरकार की विक्रेय एसएलआर दिनांकित प्रतिभूतियों में रूपांतरण और अनुसूचित बैंकों की 5 वर्ष से अन्यून अवधिवाली सावधि जमाओं को आयकर अधिनियम की धारा 80 सी में शामिल करना ।

3.92 ब्याज दरों की अनिश्चितता, अमरीकी फेड दर में वृद्धि, कुछ बड़े बैंकों के आशा से कम वित्तीय नतीजे, बैंकों की निधियों की लागत में वृद्धि की चिंताएं, ऋण के लिए अधिक प्रावधान और निवेश के ह्रास के कारण बैंकों के लाभ में कमी जैसे अनेक कारकों के कारण बाजार सहभागियों ने बैंकों के भावी अर्जन की प्रत्याशाओं को जनवरी 2006 से नीचे की ओर आने की समीक्षा की। इसको परिलक्षित करते हुए, जनवरी से जून 2006 के दौरान बैंकिंग क्षेत्र के शेयरों की बाजार में अच्छी स्थिति नहीं रही। लेकिन, बैंक के शेयर अधिक अर्जन की सुदृढ़ प्रत्याशाओं और शेयर बाजार में समग्र सुधार के कारण जुलाई 2006 की शुरुआत में सुधरे। बैंक के शेयरों ने, जो 2005-06 के दौरान सामान्य बाजार और महत्वपूर्ण क्षेत्रीय सूचकाकों से तुलना करने पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, 2006-07 (अप्रैल-सितंबर) के दौरान बाजार और क्षेत्रीय सूचकाकों - दोनों में अच्छा प्रदर्शन किया (सारणी III.42)।

3.93 2005-06 के दौरान बैंक के शेयरों द्वारा अर्जित 36.8 प्रतिशत आय पिछले वर्ष (28.6 प्रतिशत) से अधिक थी। जब बैंक के शेयरों की कम परिवर्तनशीलता (सह-संबंध गुणांक अंतर के अनुसार मापित) के साथ देखा गया तो 2005-06 के दौरान आय में वृद्धि खास तौर से उल्लेखनीय थी (सारणी III.43)।

सारणी III.42: बैंकिंग स्टॉकों पर प्रतिलाभ*

(प्रतिशत)

	मुंबई स्टाक एक्सचेंज	मुंबई स्टाक एक्सचेंज 500	क्षेत्र संबंधी सूचकांक					
			बैंकेक्स	एफएमसीजी	सूचना प्रोद्योगिकी	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	पूंजीगत वस्तुएं	उपभोक्ता टिकाउ वस्तुएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2002-03	-12.1	-8.0	16.2	-23.5	-20.4	10.1	26.4	15.1
2003-04	83.4	109.4	118.6	31.3	29.2	148.1	147.3	68.4
2004-05	16.1	21.9	28.6	11.6	59.5	8.1	39.9	50.5
2005-06	73.7	65.2	36.8	109.9	49.2	44.0	156.0	115.4
2006-07 (अप्रैल-सितंबर)	10.4	4.9	14.7	-6.6	9.0	-4.9	0.4	-3.4

* सूचकांक में प्रतिशत अंतर बिंदु-दर-बिंदु आधार पर मापा गया है ।

सारणी III.43: बैंक स्टॉकों का कार्यनिष्पादन - जोखिम और प्रतिलाभ

सूचकांक	प्रतिलाभ*		अस्थिरता@	
	2004-05	2005-06	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5
बैंकेक्स	28.6	36.8	17.1	11.8
मुंबई स्टाक एक्सचेंज सेंसेक्स	16.1	73.7	11.2	16.7

* : सूचकांकों में प्रतिशत अंतर बिंदु-दर-बिंदु आधार पर।
@ : सहसंबंध के गुणांक।

3.94 वैयक्तिक बैंक स्तर पर, ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स, करूर वैश्य बैंक लि. और बैंक ऑफ पंजाब लि. को छोड़कर, 2005-06 के दौरान सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के अधिकांश बैंकों के शेयरों में मुनाफा दिखा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में, 2005-06 के दौरान बड़े मुनाफाकर्ता बैंक थे : स्टेट बैंक ऑफ मैसूर (90.3 प्रतिशत), बैंक ऑफ इंडिया (72.8 प्रतिशत), सिंडीकेट बैंक (71.3 प्रतिशत), इलाहाबाद बैंक (65.8 प्रतिशत), इंडियन ओवरसीज बैंक (57.7 प्रतिशत), आंध्रा बैंक (53.3 प्रतिशत), स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर (52.2 प्रतिशत) और भारतीय स्टेट बैंक (49.6 प्रतिशत)। निजी क्षेत्र के बैंकों में, 2005-06 के दौरान बड़े लाभकर्ता बैंकों में कोटक महिंद्रा बैंक लि. (115.6 प्रतिशत) कर्नाटक बैंक लि. (94.1 प्रतिशत), सेंचूरियन बैंक ऑफ पंजाब लि. (73.6 प्रतिशत), यूटीआई बैंक लि. (70.6 प्रतिशत), आईसीआईसीआई बैंक लि. (63.5 प्रतिशत) और एचडीएफसी बैंक लि.(50.5 प्रतिशत) शामिल थे। सार्वजनिक और निजी दोनों- क्षेत्र के बैंकों का कीमत/ अर्जन अनुपात व्यापक था। मार्च 2006 के अंत में, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का कीमत/अर्जन अनुपात 5.0 और 26.0 प्रतिशत के रेंज में थे,लेकिन, निजी क्षेत्र के बैंकों का कीमत/ अर्जन अनुपात 4.8 और 143.6 प्रतिशत के रेंज में था जिसमें एक बैंक (यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक) का कीमत/अर्जन अनुपात नकारात्मक था (सारणी III.44)।

3.95 बैंकों के शेयरं मार्च 2006 के अंत में भारतीय इक्विटी बाजार के बाजार पूंजीकरण का बड़ा हिस्सा थे, यद्यपि उनका हिस्सा कुछ कम हो गया। कुल टर्नओवर में बैंक के शेयरों के टर्नओवर का हिस्सा 2005-06 और 2006-07 में गिरा (अगस्त तक) (सारणी III.45)।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में शेयरधारिता पैटर्न

3.96 2005-06 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के स्वामित्व के विविधीकरण की प्रक्रिया जारी रही। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या, जिनमें निजी शेयर होल्डिंग 40-49 प्रतिशत के रेंज में थी, मार्च 2005 के अंत में छह से बढ़कर मार्च 2006 के अंत में 11 हो गई। सार्वजनिक क्षेत्र के तीन बैंकों में, निजी शेयर होल्डिंग 30-40 प्रतिशत के रेंज में और शेष तीन में 20-30 प्रतिशत के रेंज में थी।

सारणी III.44: बीएसई में बैंकों के शेयर का मूल्य और मूल्य/अर्जन अनुपात

बैंक का नाम	औसत दैनिक बंद मूल्य (रु.)		पी/ई अनुपात मार्च के अंत में	
	2004-05	2005-06	2005	2006
1	2	3	4	5
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक				
इलाहाबाद बैंक	51.5	85.4	6.2	5.0
आंध्र बैंक	62.8	96.3	8.3	8.1
बैंक ऑफ बड़ौदा	191.1	226.2	9.5	10.4
बैंक ऑफ इंडिया	67.7	117.0	14.8	9.2
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	30.3	33.4	8.0	26.0
केनरा बैंक	163.6	225.2	7.4	8.2
कार्पोरेशन बैंक	297.6	370.6	12.4	12.3
देना बैंक	28.9	32.9	15.0	14.3
इंडियन ओवरसीज बैंक	57.0	89.9	6.4	6.7
ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	276.9	260.5	8.2	10.6
पंजाब नैशनल बैंक	322.9	420.4	8.8	10.3
सिंडिकेट बैंक	44.2	75.7	6.3	8.7
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	81.9	118.5	7.2	9.1
विजया बैंक	55.2	60.5	7.3	18.0
भारतीय स्टेट बैंक	542.5	811.7	8.0	11.6
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	2,044.2	2,757.4	5.7	14.4
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	1,845.5	3,513.3	3.5	10.6
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	1,772.0	2,697.7	4.1	8.0
युको बैंक	24.2	28.0	7.0	9.1
निजी क्षेत्र के बैंक				
बैंक ऑफ राजस्थान लि.	45.5	52.1	17.3	31.2
सिटी यूनियन बैंक लि.	75.9	97.8	4.4	4.8
धनलक्ष्मी बैंक	25.4	31.8	-4.1	10.5
फेडरल बैंक लि.	122.0	175.6	11.2	7.7
आईएनजी बैंक	129.5	158.4	-36.7	143.6
इंडसिंड बैंक लि.	48.9	61.4	7.1	36.9
जम्मू और कश्मीर बैंक लि.	329.8	442.3	15.3	12.4
कर्नाटक बैंक लि.	52.9	102.7	5.8	6.9
करूर वैश्य बैंक लि.	360.6	240.4	7.0	6.5
कोटक महिंद्र बैंक लिमि.	89.5	193.0	49.5	72.7
साउथ इंडियन बैंक लि.	56.9	65.7	35.1	8.5
युनाइटेड वेस्टर्न बैंक	34.8	37.5	-1.4	-2.4
New Private Sector Banks				
बैंक ऑफ पंजाब लिमि.*	25.5	19.1	-5.4	42.6
सेंट्रल बॅंक ऑफ पंजाब लिमि.	11.0	19.1	60.3	42.6
एचडीएफसी बैंक लि.	437.4	658.5	25.3	27.8
आइसीआइसीआइ बैंक लि.	309.7	506.3	14.4	20.6
यूटीआइ बैंक लि.	160.3	273.1	19.8	20.5
यस बैंक	–	72.1	–	49.0

* : 1 अक्तूबर 2005 को बैंक ऑफ पंजाब लि. का सेंचुरियन बैंक लि. के साथ विलय कर दिया गया।
टिप्पणी : औसत की गणना दैनिक बंद मूल्य पर की गई है।
स्रोत : मनी लाइन टेलरेट एण्ड प्रोवेस डेटाबेस सीएसआइई।

सारणी III.45: बैंक स्टाकों का संबंधित अंश - कुल पण्यावर्त तथा बाजार पूंजीकरण

(प्रतिशत)

वर्ष	कुल पण्यावर्त में बैंक स्टाकों के पण्यावर्त का अंश	कुल बाजार पूंजीकरण में बैंक स्टाकों के पूंजीकरण का अंश
1	2	3
2004-05	10.8	8.6
2005-06	6.8	7.1
2006-07 (अप्रैल-सितंबर)	4.7	7.6

* : अवधि के अंत में

टिप्पणी : बैंकों के पण्यावर्त और बाजार पूंजीकरण के एनएसइ के आंकड़े सीएनएक्स बैंको से संबंधित हैं।

तथापि, अब भी सार्वजनिक क्षेत्र के 4 ऐसे बैंक थे जिनकी सरकारी शेयर होल्डिंग 90 प्रतिशत से अधिक थी (सारणी III.46 और परिशिष्ट सारणी III.31)।

3.97 2005-06 के दौरान भारतीय बैंकों में विदेशी वित्तीय संस्थाओं ने रुचि दिखाना जारी रखा। मार्च 2006 के अंत में, 20 ऐसे भारतीय बैंक थे (सार्वजनिक क्षेत्र के बारह बैंक, निजी क्षेत्र के पाँच नए बैंक और निजी क्षेत्र के तीन पुराने बैंक) जिनमें वित्तीय संस्थाओं (अनिवासी) की शेयर होल्डिंग 10 प्रतिशत से अधिक थी (सारणी III.47)।

7. बैंकों में प्रोद्योगिकी विकास

3.98 हाल के वर्षों में वित्तीय प्रणाली की कार्यक्षमता के सुधार में प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसको उत्पादों की उचित रूप से विस्तृत सीमा प्रदान करने तथा जनसंख्या की बहुत बड़ी संख्या को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के एक उत्कृष्ट उपकरण के रूप में भी देखा जा रहा है। भारतीय बैंकिंग क्षेत्र ने कागज आधारित लेन देनों से (जिनमें मुद्रा, चेक अथवा चालान शामिल हैं) इलेक्ट्रानिक साधन (जिसमें तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) और राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण (एनईएफटी) और अन्य इलेक्ट्रानिक तरीके शामिल हैं) में अंतरण के रूप में बड़ी लंबी छलांग लगाई है। 2005-06 में बैंकिंग कारोबार के कंप्यूटराइजेशन को अधिक महत्व दिया गया। इस प्रयोजन के लिए, बैंकों ने प्रौद्योगिकी में बहुत अधिक निवेश किया। सितंबर 1999 और मार्च 2006 के बीच, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने कंप्यूटराइजेशन और संचार नेटवर्क के विकास के लिए 10,676 करोड़ रुपए का व्यय किया (परिशिष्ट सारणी III.32)।

सारणी III.46: सरकारी क्षेत्र के बैंकों में निजी शेयर धारिता*

(31 मार्च, 2006 को)

श्रेणी	बैंकों की संख्या
1	2
10 प्रतिशत तक	4
10 से ऊपर तथा 20 प्रतिशत तक	–
20 से ऊपर तथा 30 प्रतिशत तक	3
30 से ऊपर तथा 40 प्रतिशत तक	3
40 से ऊपर तथा 49 प्रतिशत तक	11

– : शून्य/ नगण्य

* : 19 राष्ट्रीयकृत बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और आइडीबीआइ लि. सहित।

सारणी III.47: भारतीय बैंकों में विदेशी संस्थाओं (अनिवासी) की शेयर धारिता

(31 मार्च, 2006 को)

श्रेणी	बैंकों की संख्या		
	सरकारी क्षेत्र के बैंक	निजी क्षेत्र के नए बैंक	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक
1	2	3	4
कुछ नहीं	14	3	11
10 प्रतिशत तक	2	–	4
10 से ऊपर तथा 20 प्रतिशत तक	10	2	1
20 से ऊपर तथा 30 प्रतिशत तक	2	1	1
30 से ऊपर तथा 40 प्रतिशत तक	–	–	–
40 से ऊपर तथा 50 प्रतिशत तक	–	1	1
50 से ऊपर तथा 60 प्रतिशत तक	–	–	–
60 से ऊपर तथा 70 प्रतिशत तक	–	–	–
70 से ऊपर तथा 80 प्रतिशत तक	–	1	–

3.99 हाल के वर्षों में 'कोर बैंकिंग सोल्यूशन' (सीबीएस) प्रदान करने वाली शाखाओं की संख्या काफी बढ़ी है। सीबीएस अनेक लाभ प्रदान करता है जैसे 'एनीव्हेयर बैंकिंग', एनीव्हेयर एक्सेसट और इष्टतम लागत और दक्षतापूर्वक निधियों का तुरंत अंतरण। जबकि निजी क्षेत्र के नए बैंकों, विदेशी बैंकों और निजी क्षेत्र के कुछ पुराने बैंकों में पहले से ही 'कोर बैंकिंग सोल्यूशन' कार्य कर रहा है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक व्यापक रूप से इस प्रणाली को अपना रहे हैं। सीबीएस प्रदान करने वाली शाखाओं की कुल संख्या 31 मार्च 2005 के 11.0 प्रतिशत से बढ़कर 31 मार्च 2006 को 28.9 प्रतिशत हो गई (सारणी III.48 और परिशिष्ट सारणी III.33)। वर्ष के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड शाखाएं खोलकर सीबीएस को अपनाया।

सारणी III.48: सरकारी क्षेत्र के बैंकों में कंप्यूटरीकरण

(31 मार्च, 2006 को)

(प्रतिशत)

1	2
i) पहले से ही पूर्णतः कंप्यूटरीकृत शाखाएं #	48.5
ii) कोर बैंकिंग समाधान युक्त शाखाएं	28.9
iii) पूर्णतः कंप्यूटरीकृत शाखाएं (i+ii)	77.5
iv) अंशतः कंप्यूटरीकृत शाखाएं	18.2

: कोर बैंकिंग समाधान युक्त शाखाओं से भिन्न।

3.100 मार्च 2006 के अंत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की 95 प्रतिशत से अधिक शाखाएं पूरी तरह से अथवा आंशिक रूप से कंप्यूटराइज्ड थीं। सार्वजनिक क्षेत्र के 27 बैंकों में से दस बैंकों की शाखाएं 100 प्रतिशत कंप्यूटराइज्ड थीं जबकि अन्य 12 बैंकों की 50 प्रतिशत से अधिक शाखाएं कंप्यूटराइज्ड थीं (सारणी III.49)। सार्वजनिक क्षेत्र के केवल पाँच बैंकों की 50 प्रतिशत से कम शाखाएं कंप्यूटराइज्ड थीं।

3.101 मार्च 2006 के अंत में बैंकों द्वारा लगाए गए एटीएम की कुल संख्या 21,147 थी। राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा लगाए गए एटीएम सर्वाधिक संख्या में थे, इसके पश्चात निजी क्षेत्र के नए बैंक, एसबीआई समूह, निजी क्षेत्र के पुराने बैंक और विदेशी बैंक थे (सारणी III.50)। जबकि एसबीआई समूह, निजी क्षेत्र के नए बैंकों और विदेशी बैंकों के ऑफ साइट एटीएम अधिक थे, राष्ट्रीयकृत और निजी क्षेत्र के पुराने बैंकों के ऑन साइट एटीएम अधिक थे (चार्ट III.22)।

3.102 कुल शाखाओं के प्रतिशत के रूप में विदेशी बैंकों के सर्वाधिक ऑफ साइट एटीएम थे। इसके पश्चात एसबीआई समूह, निजी क्षेत्र के नए बैंकों, निजी क्षेत्र के पुराने बैंकों और राष्ट्रीयकृत बैंकों का स्थान था (परिशिष्ट सारणी III.34)।

सारणी III.49: शाखाओं का कंप्यूटरीकरण - सरकारी क्षेत्र के बैंक

(31 मार्च, 2006 को)

कंप्यूटरीकरण की मात्रा	बैंकों की संख्या
1	2
कुछ नहीं	–
10 प्रतिशत तक	1
10 से ऊपर तथा 20 प्रतिशत तक	–
20 से ऊपर तथा 30 प्रतिशत तक	2
30 से ऊपर तथा 40 प्रतिशत तक	2
40 से ऊपर तथा 50 प्रतिशत तक	–
50 से ऊपर तथा 60 प्रतिशत तक	3
60 से ऊपर तथा 70 प्रतिशत तक	2
70 से ऊपर तथा 80 प्रतिशत तक	2
80 से ऊपर तथा 90 प्रतिशत तक	–
90 से ऊपर तथा 100 प्रतिशत से कम	5
पूर्णतः कंप्यूटरीकृत	10
जोड़ *	**27**

* : आइडीबीआइ को छोड़ कर।

3.103 क्रेडिट कार्ड और प्रौद्योगिकी उन्नति की सुविधा और सरल स्वीकार्यता के फलस्वरूप फुटकर इलेक्ट्रानिक और कार्ड-आधारित भुगतान प्रणाली में निरंतर वृद्धि हुई है। कार्ड और इलेक्ट्रानिक आधारित भुगतानों की मात्रा और मूल्य पिछले वर्ष से 2006 में दो गुने से अधिक हो गए (सारणी III.51)।

3.104 फुटकर लेनदेनों में इलेक्ट्रानिक और कार्ड-आधारित भुगतानों के बढ़ते प्रयोग को देखते हुए, कुल लेनदेनों में उनका हिस्सा 2006 में मात्रा के अनुसार 46.7 प्रतिशत और मूल्य के अनुसार 51.2 प्रतिशत था। पिछले वर्ष से तुलना करने पर 2005-06 के दौरान भुगतान की

सारणी III.50: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की शाखाएं और एटीएम

(मार्च 2006 के अंत में)

बैंक समूह	शाखाओं की संख्या					एटीएम की संख्या प्रतिशत			कुल शाखाओं के प्रतिशत के रूप में परोक्ष रूप के एटीएम
	ग्रामीण	अर्ध-शहरी	शहरी	महा-नगरीय	कुल	प्रत्यक्ष रूप के	परोक्ष रूप के	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
i) राष्ट्रीयकृत बैंक	12,992	7,120	7,056	7,017	34,185	4,812	2,353	7,165	32.8
ii) स्टेट बैंक समूह	5,229	4,043	2,449	2,110	13,831	1,775	3,668	5,443	67.4
iii) निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	936	1,447	1,236	947	4,566	1,054	493	1,547	31.9
iv) निजी क्षेत्र के नए बैंक	97	322	674	857	1,950	2,255	3,857	6,112	63.1
v) विदेशी बैंक	–	1	37	221	259	232	648	880	73.6
जोड़ (i to v)	**19,254**	**12,933**	**11,452**	**11,152**	**54,791**	**10,128**	**11,019**	**21,147**	**52.1**

सारणी III.51: फुटकर इलेक्ट्रॉनिक तथा कार्ड आधारित भुगतान

(मात्रा हजार एवं मूल्य करोड़ रुपए)

वर्ष	फुटकर इलेक्ट्रॉनिक @		कार्ड आधारित #		कुल	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
2001-02	178	6,123	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	178	6,123
2002-03	237	10,222	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	237	10,222
2003-04	290	29,606	1862	35,889	2,152	65,496
2004-05	579	77,702	3615	77,267	4,194	1,54,969
2005-06	832	1,06,599	10453	2,36,994	11,286	3,43,593

उ.न. : उपलब्ध नहीं।
@ : ईसीएस (नामे और जमा),ईएफटी तथा एसईएफटी।
# : क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और स्मार्ट कार्ड।
टिप्पणी : मात्रा लेनदेन की संख्या से संबंधित है।

इलेक्ट्रानिक प्रणाली का प्रयोग मात्रा और मूल्य- दोनों के अनुसार बढ़ा (सारणी III.52.चार्ट III.23)।

चार्ट III.22: एटीएम-बैंक समूहवार अंश
(मार्च 2006 के अंत में)

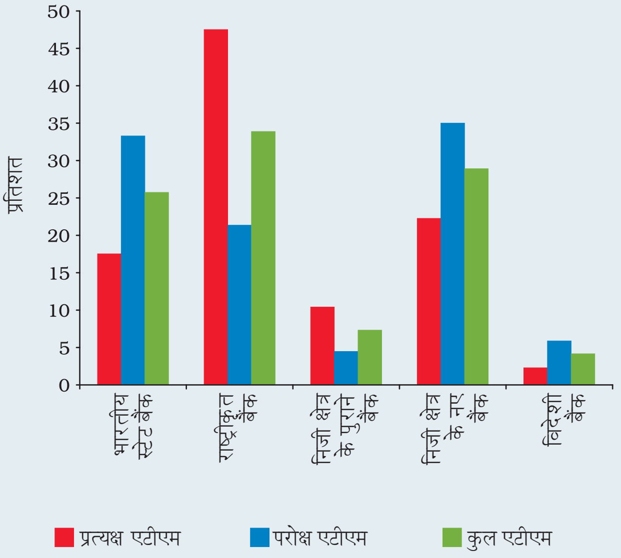

3.105 आरटीजीएस 26 मार्च 2004 को शुरू किया गया। निधियों के अंतरण के लिए इसका प्रयोग, खास तौर से बड़े मूल्यों और प्रणालीगत महत्वपूर्ण प्रयोजनों के लिए तब से बढ़ गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक के सभी केन्द्रों ने अंतर-बैंक कागज आधारित समाशोधन जून 2005 से बंद कर दिया। सभी अंतर-बैंक लेन-देन अब आरटीजीएस

सारणी III.52: कागज आधारित बनाम इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन

वर्ष	कागज आधारित	इलेक्ट्रॉनिक	कुल
1	2	3	4
		मात्रा (लाख रुपए)	
2002-03	10,139	1,730	11,869
2003-04	10,228	2,152	12,380
2004-05	11,671	4,200	15,871
2005-06	12,895	11,300	24,195
		मूल्य (करोड रुपए)	
2002-03	1,34,24,313	37,536	1,34,61,849
2003-04	1,15,95,960	67,461	1,16,63,421
2004-05	1,01,20,716	42,21,153	1,43,41,869
2005-06	1,13,37,062	1,18,84,429	2,32,21,491

चार्ट III.23: पेपर आधारित बनाम इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन - तुलनात्मक प्रवाह (मूल्य)

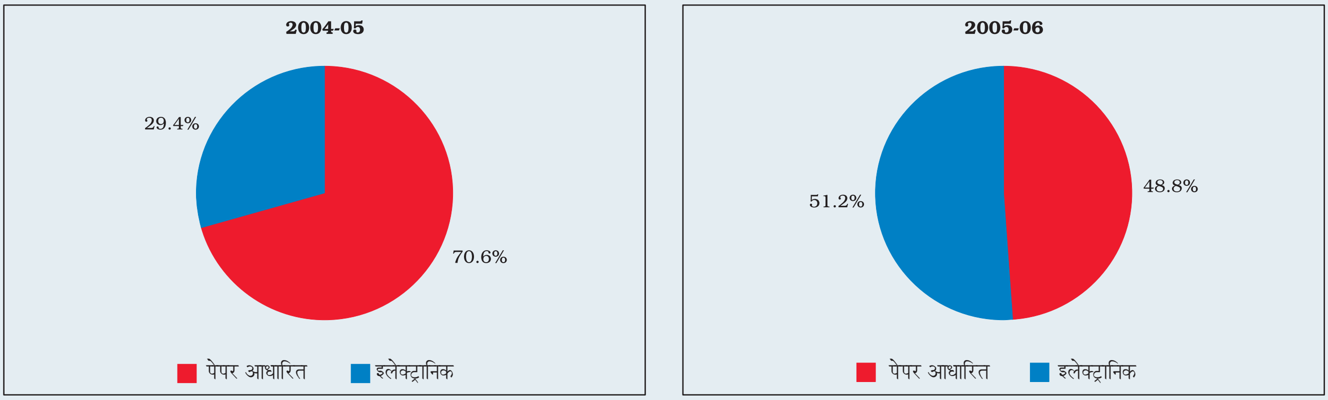

चार्ट III.24: आरटीजीएस में प्रगति

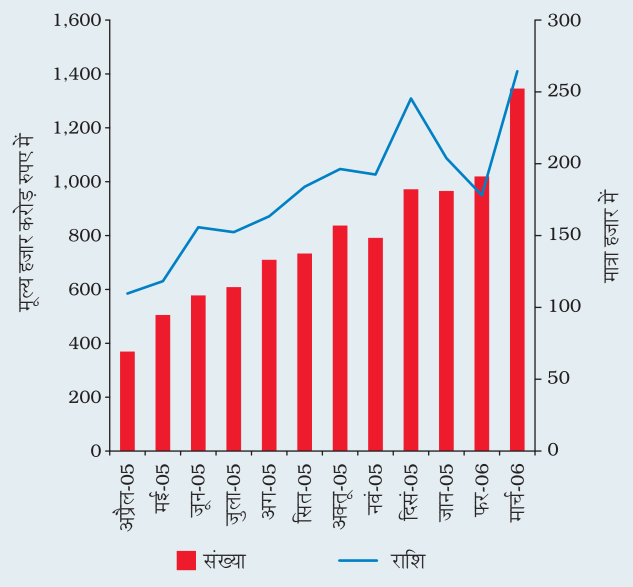

चार्ट III.25: बैंक समूहवार शाखा वितरण

(जून 2006 के अंत में)

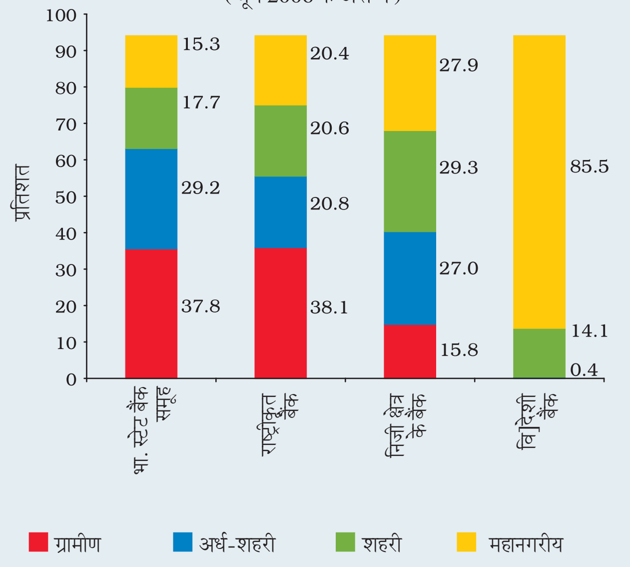

के माध्यम से किये जाते हैं। अंतर बैंक निधियों के अंतरण के अलावा, आरटीजीएस प्रणाली ग्राहक लेन-देनों को सुगम बनाती है। मार्च 2005 के अंत में, आरटीजीएस शाखाओं की संख्या लगभग 23000 हो गई। मार्च 2006 के अंत तक लेन-देनों की संख्या 200,000 को पार कर गई (चार्ट III.24)।

8. बैंकों का क्षेत्रीय विस्तार

3.106 जून 2006 के अंत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं की कुल संख्या, जून 2005 के अंत में 68,549 से बढ़कर 69, 417 हो गई जिसमें 30,776 ग्रामीण शाखाएं, 15,370 अर्द्ध-शहरी शाखाएं तथा 23,271 शहरी और महानगरीय शाखाएं शामिल हैं। ग्रामीण शाखाओं का हिस्सा पिछले वर्ष के 44.9 प्रतिशत से गिरकर 2005-06 के दौरान 44.3 प्रतिशत हो गया जबकि महानगरीय शाखाओं की संख्या थोड़ी सी बढ़कर 16.0 प्रतिशत से 16.2 प्रतिशत हो गई। वर्ष के दौरान अर्द्ध शहरी और शहरी शाखाओं का हिस्सा क्रमश: 22.0 प्रतिशत और 17.0 प्रतिशत के लगभग अपरिवर्तित बना रहा। ग्रामीण शाखाओं के हिस्से में गिरावट का कारण शहरी और महानगरीय केंद्रों में खोली गई नई शाखाओं की बड़ी संख्या थी (चार्ट III.25 और परिशिष्ट सारणी III.35)।

3.107 मार्च 2006 के अंत में जमाओं के आकार के अनुसार ऊपर से क्रमबद्ध सौ केंद्रों की जमाराशियां कुल जमाराशियों की 67.0 प्रतिशत थीं और बैंक ऋण के आकार के अनुसार ऊपर से क्रमबद्ध सौ केंद्रों के ऋण कुल बैंक ऋणों के 76.5 प्रतिशत थे (सारणी III.53) । कुल जमाओं और कुल बैंक ऋणों में ऊपर के सौ केंद्रों का हिस्सा मार्च 2005 के अंत में अपने संबंधित स्तर से बढ़ा ।

3.108 दक्षिणी क्षेत्र में बैंक की विद्यमान शाखाओं के होने का सर्वाधिक प्रतिशत था, इसके पश्चात केंद्रीय, पूर्वी -उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र थे। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र का हिस्सा मार्च 2006 के अंत में कम अर्थात 2.8 प्रतिशत रहा। 2005-06 के दौरान, उत्तरी (286) और दक्षिणी (252) क्षेत्र में बहुसंख्या में नई शाखाएं खोली गई। विभिन्न क्षेत्रों में बैंक की एकल शाखा द्वारा कवर की जा रही जनसंख्या का औसत न्यूनाधिक रूप से पिछले वर्ष के स्तर पर रहा। (चार्ट III.26 और परिशिष्ट सारणी III/36)।

सारणी III.53: कुल जमाराशियों में तथा समग्र बैंक क्रेडिट में चरम स्तर के सौ केंद्रों का हिस्सा

(प्रतिशत)

मार्च के अंत में	जमाराशियां		क्रेडिट	
	कार्यालय	राशि	कार्यालय	राशि
1	2	3	4	5
1999	21.5	59.1	21.1	73.5
2000	21.9	59.0	21.5	74.7
2001	22.3	58.9	21.9	75.3
2002	22.5	59.1	22.1	77.0
2003	22.7	61.0	22.4	75.9
2004	23.1	63.6	22.9	75.5
2005	23.8	65.3	23.7	75.9
2006	24.2	67.0	24.0	76.5

स्रोत : मूल सांख्यिकी विवरणी - 7

चार्ट III.26: बैंक शाखाओं का क्षेत्रीय वितरण

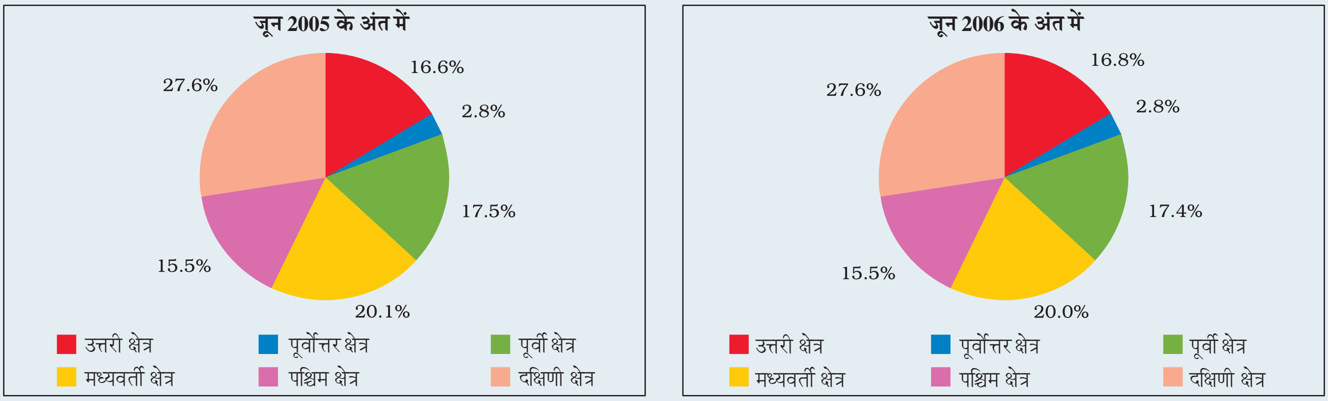

3.109 अखिल भारतीय ऋण-जमा अनुपात (मंजूरियों के अनुसार) मार्च 2005 के अंत में 66.0 प्रतिशत से तेजी से बढ़कर मार्च 2006 के अंत में 72.5 प्रतिशत हो गया। पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों का ऋण जमा अनुपात और निवेश प्लस (+) ऋण - जमा अनुपात अखिल भारतीय स्तर से अधिक बना रहा ((चार्ट III.27)।अधिकांश राज्यों का ऋण-जमा अनुपात अखिल भारतीय प्रवृत्ति के अनुसार बढ़ा, लेकिन, कुछ राज्यों (जैसे चंडीगढ़, दमन और दीव, गोवा, जम्मू और कश्मीर, मेघालय और नागालैंड) के ऋण जमा अनुपात में मध्यम से तेज गति गिरावट आई (परिशिष्ट सारणी III.37) । आंध्रा प्रदेश, चंडीगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु सहित छह राज्यों / संघशासित प्रदेशों का ऋण जमा अनुपात अखिल भारतीय स्तर की तुलना में अधिक था।

चार्ट III.27: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का क्षेत्रवार ऋण-जमा तथा निवेश और ऋण-जमा अनुपात

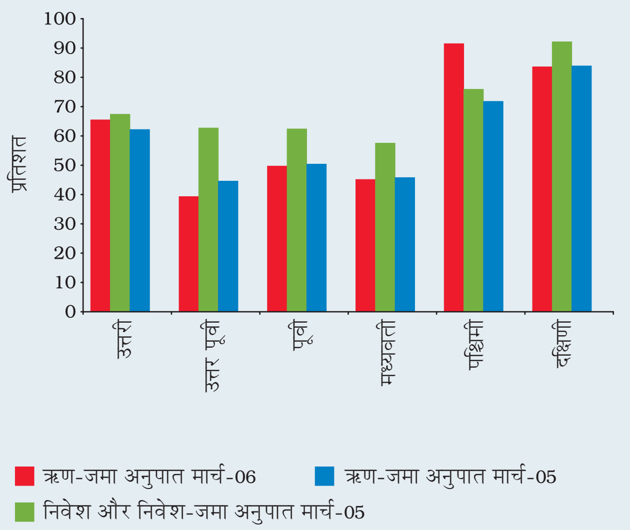

भारत में विदेशी बैंकों का परिचालन

3.110 30 सितंबर 2006 की स्थिति के अनुसार भारत में कार्य करने वाले विदेशी बैंकों की कुल संख्या 29 थी। ये बैंक 19 देशों के थे। विदेशी बैंकों की 258 शाखाएं 19 राज्यों /संघशासित प्रदेशों के 40 केंद्रों में फैली थीं। जबकि मार्च 2006 के अंत में चार बैंकों की 10 या अधिक शाखाएं थी, नौ बैंकों में से प्रत्येक केवल एक-एक शाखा के साथ कार्य कर रहे थे। जुलाई 2005 और जून 2006 के दौरान, भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों को 13 अतिरिक्त शाखाएं खोलने की अनुमति प्रदान की गई।

3.111 आइएनजी बैंक एन.वी.ने 28 अक्तूबर 2005 से भारत में बैंकिंग कार्य बंद कर दिये । बैंक ऑफ टोकियो-मित्सुबिशी लि. ने 1 जनवरी 2006 से अपने बैंकिंग कारोबार का वैश्विक स्तर पर यूएफजे बैंक लि. के साथ विलय कर दिया और विलय की गई नई कंपनी को 'द बैंक ऑफ मित्सुबिशी यूएफजे लि.' कहा जाता है। तदनुसार, दूसरी अनुसूची से यूएफजे बैंक लि. को निकालने का निदेश देने और नई कंपनी के नाम में परिवर्तन की सूचना देने संबंधी अधिसूचना भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(6) (ख) और (ग) के अंतर्गत जारी की गई । भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 42(6) (ग) के अंतर्गत चोहुंग बैंक को 'सिन्हान बैंक' के रूप में अपने नाम में परिवर्तन करने की भी अनुमति प्रदान की गई और 25 जुलाई 2006 को इससे संबंधित अधिसूचना जारी की गई।

3.112 सात विदेशी बैंकों, अर्थात कामनवेल्थ बैंक आफ आस्ट्रेलिया, बांश पोपुलरी, यूनाइट एस सीआरएल, नेशटोर्ग बैंक, प्रोम्सव्याज बैंक, बैंका पोपुलेर डि विसेंजा, मांटे डेइ पास्ची डाइ सियना और जुरकर कोंटानाल बैंक ने भारत में प्रतिनिधि कार्यालय खोले । तीन प्रतिनिधि कार्यालयों, अर्थात बाडेन रुट्टेम वर्गिसचे बैंक ए.जी., यूनियन बैंक ऑफ कैलिफोर्निया और मिज़ूहो कारपोरेट बैंक लि., ने भारत में अपने

परिचालन बंद कर दिए। बाडेन हेमवर्गिसचे बैंक ए.जी. और यूनियन बैंक ऑफ कैलिफोर्निया का क्रमशः लैंड्स बैंक बाडेन वुरथेमवर्ग, ए.जी. और वाचोंविया बैंक में विलय हो गया। 15 सितंबर 2006 को, भारत में 14 देशों के 31 बैंकों के प्रतिनिधि कार्यालय थे। इस प्रकार, कुल मिलकर, भारत में 60 विदेशी बैंक या तो शाखाओं के रूप में अथवा प्रतिनिधि कार्यालयों के रूप में मौजूद थे (सारणी III.54) ।

विदेशों में भारतीय बैंकों के परिचालन कार्य

3.113 30 सितंबर 2006 की स्थिति के अनुसार अठारह भारतीय बैंक विदेशों में कार्य कर रहे थे जिनकी 47 देशों में 112 शाखाएं (आफशेर इकाइयों सहित) 6 संयुक्त उद्यम, 18 सहायक कंपनियां और 35 प्रतिनिधि कार्यालय कार्य कर रहे थे (सारणी III.55)। बैंक ऑफ बड़ौदा की विदेशों में सर्वाधिक उपस्थिति थी जिसकी 20 देशों में 39 शाखाएं, 7 सहायक कंपनियां, एक संयुक्त उद्यम बैंक और 3 प्रतिनिधि कार्यालय थे। इसके पश्चात भारतीय स्टेट बैंक था जिसकी 29 देशों में 30 शाखाएं, पांच सहायक कंपनियां, तीन संयुक्त उद्यम बैंक और सात प्रतिनिधि कार्यालय थे। इसके बाद, बैंक ऑफ इंडिया था जिसकी 14 देशों में 20 शाखाएं, एक सहायक कंपनी, दो संयुक्त उद्यम बैंक और तीन प्रतिनिधि कार्यालय थे।

सारणी III.54: भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों की देशवार सूची

(सितंबर 2006 के अंत में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	निगमित देश	भारत में शाखाओं की संख्या
1	2	3	4
1	एबीएन एमरो बैंक एनवी	नीदरलैंड	24
2	आबू धाबी कमर्शियल बैंक लि.	यूएई	2
3	अरब बांग्लादेश बैंक लि.	बांग्लादेश	1
4	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक लि.	यूएसए	7
5	एंटवेर्प डायमंड बैंक	बेल्जियम	1
6	बैंक इंटरनेशनल इंडोनेशिया	इंडोनेशिया	1
7	बैंक ऑफ अमरीका	यूएसए	5
8	बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत बी एस सी	बहरीन	2
9	बैंक ऑफ नोवा स्कॉटिया	कनाडा	5
10	बैंक ऑफ टोकियो-मित्सुबिशी लिमि.	जापान	3
11	बीएनपी परिबास	फ्रांस	8
12	बैंक ऑफ सिलोन	श्रीलंका	1
13	बरकलेज बैंक पीएलसी	यूके	1
14	काल्यन बैंक	फ्रांस	5
15	सिटी बैंक एन ए	यूएसए	39
16	शिन हंग बैंक	साउथ कोरिया	1
17	चाइनाट्रस्ट कमर्शियल बैंक	ताईवान	1
18	ड्यूश बैंक	जर्मनी	8
19	डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लि.	सिंगापुर	2
20	एचएसबीसी बैंक लि..	हांगकांग	45
21	जेपी मोर्गन चेस बैंक	यूएसए	1
22	क्रुंग थाई बैंक पब्लिक कं. लि.	थाईलैंड	1
23	मिज़ुओ कार्पोरेट बैंक लिमि.	जापान	2
24	मशरेक बैंक पीएसस	यूएई	2
25	ओमान इंटरनेशनल बैंक एसएओजी	सुल्तान ऑफ ओमान	2
26	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	यूके	81
27	सोनाली बैंक	बांग्लादेश	2
28	सोसाइटे जनरेल	फ्रांस	2
29	स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस लि.	मॉरिशस	3
	कुल		**258**

सारणी III.55: भारतीय बैंकों का विदेश में परिचालन

(30 सितंबर, 2006 को)

(वास्तविक रूप से परिचालनात्मक)

बैंक का नाम	शाखा	सहयोगी	प्रतिनिधि-संस्था	संयुक्त कार्यालय बैंक	कुल
1	2	3	4	5	6
पंजाब नेशनल बैंक	1	–	4	1	6
भारतीय स्टेट बैंक	30	5	7	3	45
बैंक ऑफ इंडिया	20	1	4	1	26
बैंक ऑफ बड़ौदा	40	7	3	1	51
इंडियन बैंक	3	–	–	–	3
इंडियन ओवरसीज़ बैंक	5	1	2	–	8
यूको बैंक	4	–	1	–	5
केनरा बैंक	1	1	1	–	3
सिंडिकेट बैंक	1	–	–	–	1
भारत ओवरसीज़ बैंक	1	–	–	–	1
आइसीआइसीआइ बैंक लि.	5	3	7	–	14
इंडसइंड बैंक लि.	–	–	2	–	2
सेंचूरियन बैंक ऑफ पंजाब लि. –	–	1	–	1	
एचडीएफसी बैंक लि.	–	–	1	–	1
यूटीआई बैंक लिमि.	1				1
आंध्र बैंक		1		1	
इलाहाबाद बैंक		1		1	
जोड़	**112**	**18**	**35**	**6**	**171**

– : शून्य / नगण्य।

3.114 विशेष आर्थिक क्षेत्रों में स्थापित की गई बैंकों की ऑफशोर बैंकिंग इकाइयां भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं की तरह कार्य करती है, लेकिन भारत में स्थित हैं। इन ऑफशोर बैंकिंग इकाइयों को सीआरआर और एसएलआर की अपेक्षाओं से मुक्त रखा गया है। वे अंतरराष्ट्रीय दर पर एसईजेड इकाइयों और एसईजेड़ को विकसित करनेवालों को वित्त प्रदान करती हैं। इस प्रकार, ऑफ शोर बैंकिंग इकाइयों की योजना के अंतर्गत ऐसी इकाइयां खोलने के लिए 10 बैंकों को 14 अनुमोदन प्रदान किए गए हैं। आरंभ में, 6 बैंकों अर्थात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स, पंजाब नैशनल बैंक (पीएनबी) और आईसीआईसीआई बैंक को एसईजेड में नौ आफशोर बैंकिंग इकाइयां खोलने के लिए सिद्धांततः अनुमति प्रदान की गई - सीप्ज, मुंबई में 6 और कांडला, सूरत और कोचीन में एक -एक और तदुपरांत दूसरे चरण में 2003 में पांच बैंकों (अर्थात पीएनबी, केनरा बैंक, बैंक आफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक और विजया बैंक) को पांच ओबीयू खोलने की अनुमति प्रदान की गई, नोएडा (यू.पी.) में दो, सीप्ज (मुंबई) में

तीन। विजया बैंक जिसे सीप्ज, मुंबई में एक ओबीयू खोलने की अनुमति प्रदान की गई, ने लाइसेंस का नवीकरण नहीं कराया। हाल में, 6 बैंकों अर्थात भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नैशनल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक लि. और केनरा बैंक ने अब तक सात ओबीयू खोले हैं (सितंबर 2006 तक)। कार्य कर रहे सात ओवीयू में, पाँच सीप्ज, मुंबई में और एक-एक सीप्ज, नोएडा (केनरा बैंक) और कोची, केरल (एसबीआइ) में स्थित है।

9. ग्राहक सेवा और अधिक से अधिक जनता को वित्तीय सेवाओं के दायरे में लाना

3.115 ग्राहकों के अधिकारों को सुरक्षित करने, ग्राहक सेवा की गुणवत्ता बढ़ाने और बैंकों में शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने के लिए रिज़र्व बैंक निरंतर उपाय करता रहा है। विशेष रूप से सामान्य आदमी को प्रदान की जा रही बैंकिंग सेवाओं के मुद्दे पर विचार करने के लिए रिज़र्व बैंक ने जनसेवा प्रक्रिया और निष्पादन लेखा परीक्षा समिति (अध्यक्ष : श्री एस.एस.तारापोर) नियुक्त की और एक अलग ग्राहक सेवा विभाग (सीएसडी) बनाया।

3.116 2004 से रिज़र्व बैंक वित्तीय सेवाओं का दायरा बढ़ाने के लिए सघन प्रयास कर रहा है। नवंबर 2005 में, बैंकों को खास तौर से सलाह दी गई कि वे मूल बैंकिंग सुविधाओं वाले कम अथवा शून्य शेषों और प्रभारों वाले 'नो फ्रिल्स' खाते खोलने की व्यवस्था करें जिससे ऐसे खातों को जनसंख्या के एक बहुत बड़े भाग तक पहुंच हो सके। अनेक बैंकों ने तब से मूल्यवर्धित विशेषताओं से युक्त और मूल्यवर्धित विशेषताओं से रहित ऐसे 'नो फ्रिल्स' खाते शुरु किए हैं। रिज़र्व बैंक के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार 31 मार्च 2006 तक पांच लाख 'नो फ्रिल्स' खाते खोले गए जिसमें से लगभग दो तिहाई सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पास थे और एक तिहाई निजी क्षेत्र के बैंकों के पास थे।

3.117 रिज़र्व बैंक के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों के क्षेत्राधिकार में स्थित वाणिज्यिक बैंकों के विरुद्ध 1 जुलाई 2005 से 30 जून 2006 तक की अवधि में प्राप्त शिकायतों का मिलान किया गया है और उन्हें सात बड़े शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है; अर्थात जमा खाते, प्रेषण/संग्रहण सुविधा, ऋण /अग्रिम (सामान्य और आवास ऋण), क्रेडिट कार्ड, सीधे बेचने वाले एजेंटों (डीएसए) के कार्यकलाप, ऋण की वसूली में उत्पीड़न और सामान्य/अन्य आदि। यद्यपि, कुल संख्या में, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की संख्या सर्वाधिक थी, परन्तु उनकी प्रति शाखा औसत शिकायत काफी कम अर्थात 0.02 से 0.49 थी, इसके विपरीत,निजी क्षेत्र के बैंकों के विरुद्ध 0.01 से 1.39 और विदेशी बैंकों के मामले में 0.11 से 8.59 थी। अधिकतर शिकायतें क्रेडिट कार्ड (17.20 प्रतिशत) संबंधी थीं, इसके बाद जमा खातों (16.39 प्रतिशत) की थी। क्रेडिट कार्ड से संबंधित शिकायतें बड़े पैमाने पर विदेशी बैंकों और निजी क्षेत्र के नए बैंकों के विरुद्ध थी। (परिशिष्ट सारणी III.38)

10. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

3.118 भारत में कृषि और ग्रामीण ऋण प्रदान करने के लिए, विशेष रूप से लक्ष्य समूह और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण प्रदान करने के लिए अपनाए गए बहु एजेंसी दृष्टिकोण में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का एक विशेष स्थान है। कृषि उधार पर जोर देने के लिए, सरकार ने तीन वर्ष की अवधि में बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को दोगुना करने के लिए 2004 में एक नीति की घोषणा की ।क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का मार्गदर्शन करने और कृषि के लिए ऋण प्रवाह पर निगरानी रखने के लिए, रिज़र्व बैंक ने अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में शक्ति संपन्न समितियां गठित की हैं। ग्रामीण क्षेत्र में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को ऋण सुपुर्दगी का एक महत्वपूर्ण वाहक बनाने के लिए, रिज़र्व बैंक ने 2005 में, निम्नलिखित प्रमुख विशेषताओं वाले एक विशेष पैकेज की घोषणा की। प्रथम, प्रवर्तक बैंकों को सलाह दी गई कि वे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अपने संसाधन आधार बढ़ाने के लिए ब्याज की उचित दरों पर ऋण सहायता उपलब्ध करायें। इसके अलावा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अंतर आरआरबी मीयादी धन/उधार और रेपो/सीबीएलओ बाजारों तक भी पहुंचने की अनुमति दी गई। द्वितीय, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को ऑफ साइट एटीएम स्थापित करने, डेबिट/क्रेडिट कार्ड जारी करने और सरकारी कारोबार करने के लिए अधिकृत बैंकों के उप एजेंट के रूप में पेंशन /सरकारी कारोबार करने के लिए अनुमति प्रदान की गई। तृतीय,रिज़र्व बैंक ने संकेत दिया कि उनकी वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए, मुद्रा तिजोरी खोलने के लिए आरआरबी के प्रस्तावों पर विचार किया जा सकता है। चतुर्थ, रिज़र्व बैंक आरआरबी द्वारा विदेशी मुद्रा लेनदेनों के विभिन्न कार्यों को करने के लिए विद्यमान मानदंडों की समीक्षा कर रहा है जिससे कुछ विशिष्ट प्रयोजनों जैस विदेशी शिक्षा, कारोबार यात्रा, चिकित्सा निदान और निजी यात्राओं के लिए विदेशी मुद्रा जारी करने से संबंधित चालू खाते के लेनदेन संबंधी गैर ट्रेड को करने के लिए उन्हें अनुमति दी जा सके। नीतिगत पहलों और बदलते कारोबार वातावरण के अनुसरण में आरआरबी की भूमिका और वित्तीय निष्पादन बढ़ता जा रहा है (बाक्स III.5)।

3.119 भारतीय वित्तीय प्रणाली में ऋण सुपुर्दगी को एक प्रभावी साधन के रूप में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए, भारत सरकार ने नाबार्ड, संबंधित राज्य सरकार/सरकारों और प्रवर्तक बैंक/बैंकों से परामर्श करके सितंबर 2005 में प्रवर्तक बैंकवार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के राज्य स्तर पर समामेलन की शुरुआत की (बॉक्स III.6)।

बॉक्स III.5: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की बढ़ती भूमिका

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) आरआरबी अधिनियम 1976 के अंतर्गत 1975 में खोले गए थे। आरआरबी से आशा की गई थी कि वे राज्य प्रवर्तित, क्षेत्र आधारित और ग्रामोन्मुख वाणिज्यिक बैंक के रूप में कार्य करेंगे। इस प्रकार की ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं का मूल उद्देश्य स्थानीय आवश्यकता को समझना और परिचित होना तथा कृषि, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग और अन्य उत्पादक गतिविधियों के विकास हेतु लघु और सीमांत कृषकों, कृषि मजदूरों, सामाजिक- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को ऋण प्रदान करने के लिए वैकल्पिक चैनल के रूप में प्रोफेशनल तरीके से कार्य करना था। आरआरबी से आशा की गई है कि वे ग्रामीण विकास के लिए संसाधन जुटाएं और वे उन जरूरत मंद ग्रामीण क्षेत्रों में जुटाए गए संसाधनों का नियोजन करके कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें, जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बड़े क्षेत्र में फैले होने के बावजूद कवर नहीं किए गए थे। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, आरआरबी की पूंजी 50:15:35 के अनुपात में केंद्रीय बैंक, संबंधित राज्य सरकार और प्रवर्तक बैंक के द्वारा रखी गई।

उनके पहले दशक के परिचालन के दौरान, आरआरबी का ध्यान ऋण सेवाओं को बढ़ाने पर रहा, जो 1987 तक के उनके 100 प्रतिशत से अधिक ऋण-जमा अनुपात में परिलक्षित हुआ। इसके पश्चात् ऋण -जमा अनुपात में गिरावट आई जिससे उनके कार्यों में पुनर्विन्यास परिलक्षित होता है। हालांकि, हाल के वर्षों में ऋण जमा अनुपात 2000-01 के 41.3 प्रतिशत से 2005-06 में 55.7 प्रतिशत सुधरा है। इसका परिणाम यह हुआ है कि अग्रिमों से आय का हिस्सा 2000-01 में 34.7 प्रतिशत से बढ़कर 2005-06 में 53.8 प्रतिशत हो गया है (सारणी I)। इसके विपरीत, निवेश से आय के हिस्से में 2000-01 के 60.5 प्रतिशत की तुलना में 2005-06 में 39.5 प्रतिशत की गिरावट हुई।

1991-92 में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों की शुरुआत के कारण, आरआरबी की वाणिज्यिक लाभप्रदता उभरते आर्थिक परिदृश्य में उनकी वांछित भूमिका को तय करने में एक सबसे प्रमुख कारक के रूप में सामने आई। आरआरबी की वित्तीय स्थिति मुख्य रूप से इन कारणों से कमजोर हुई : सीमित कारोबारी लोच जिसमें विस्तार/विविधीकरण की मुश्किल से कोई गुंजाइश थी, ऋणों के छोटे आकार जिसमें जोखिम बहुल अग्रिमों का अत्यधिक एक्सपोजर और वित्तीय नियोजन में प्रोफेशनल अदक्षता । क्षेत्रीय ग्रामीण

सारणी 1: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के निवेश तथा अग्रिम

(करोड़ रुपए)

मद	2000-01	2004-05	2005-06
1	2	3	4
1. निम्न से आय का अंश			
(i) अग्रिम	34.8	49.7	53.8
(ii) निवेश	60.5	42.9	39.5
2. निवेश-जमा अनुपात*	72.2	59.2	57.6
3. ऋण-जमा अनुपात	41.3	52.9	55.7

* : निवेश-जमा अनुपा = अन्य बैंक शेषों के निवेश एवं कुल जमाराशियों के अन्य निवेशों सहित।

स्रोत : नाबार्ड।

बैंकों को मजबूत करने और उनके निष्पादन को सुधारने के लिए, रिजर्व बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों दको लक्षेतर समूह को उधार देने, अपनी जमाओं और उधार दरों को अविनियमित करने और लाभदायक क्षेत्रों में अपनी अधिशेष निधियों का निवेश करने की अनुमति दी। इन उपायों को शाखाओं द्वारा तैयार की गई सुनिश्चित कारोबार योजना, लाभप्रदता प्राप्त करने के लिए समयबद्ध कार्यान्वयन, मानव संसाधन विकास कार्यक्रम और सुधार के लिए समन्वित उपकरण के रूप में संगठन विकास पहलों ने समर्थन दिया।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में जिसमें 1995-96 में 426 करोड़ रुपए की हानि हुई, अनेक सुधार और बढ़ावा देनेवाले उपाय शुरू करने के पश्चात लाभ दिखने शुरू हुए। 2003-04 के दौरान निवल लाभ बढ़कर 769 करोड़ रुपए हो गया। तत्पश्चात 2005-06 के दौरान मुख्य रूप से निवल मार्जिन में कमी और बकायों के भुगतान के कारण,यद्यपि निवल लाभ 510 करोड़ रुपए कम हुआ,लेकिन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की समग्र स्थिति में वर्षों के दौरान काफी सुधार हुआ है। प्रति शाखा और प्रति कर्मचारी दोनों के हिसाब से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की उत्पादकता 10 वर्षों के दौरान काफी बढ़ी। 2000-01 से आरआरबी के निष्पादन में सुधार खास तौर से महत्वपूर्ण है (सारणी 2)।

सारणी 2: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कारोबार एवं वित्तीय संकेतक**

संकेतक	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5	6	7
क्षे.ग्रा. बैंकों की संख्या	196	196	196	196	196	133*
निवल लाभ (करोड़ रुपए)	600.6	607.9	519.3	768.7	748.2	510.3
प्रतिशत उत्पादकता (करोड़ रुपए)	3.8	4.4	5.0	5.7	6.6	7.7
प्रति शाखा उत्पादकता[2] (करोड़ रुपए)	0.8	0.9	1.0	1.2	1.4	1.6
आस्तियों के प्रतिशत के रूप में संचित हानि	5.6	4.7	4.4	3.9	3.5	2.9
आस्तियों के प्रतिशत के रूप में वेतन	2.0	2.2	2.3	2.6	2.0	1.8
वित्तीय प्रतिफल[3] (प्रतिशत)	9.4	10.6	9.6	8.9	8.2	6.6
वित्तीय लागत[4] (प्रतिशत)	6.0	6.8	6.1	5.4	4.6	3.5
वित्तीय मार्जिन[5] (प्रतिशत)	3.4	3.8	3.5	3.5	3.6	3.1
जोखिम, परिचालन एवं अन्य लागत (प्रतिशत)	2.1	2.6	2.6	2.2	2.3	2.9
निवल मार्जिन[6] (प्रतिशत)	1.2	1.2	0.9	1.3	1.3	0.7

* : अधिस्थगन के कारण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या घट गई, जो सितंबर 2005 में शुरू किया गया।

टिप्पणी :

1 रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान प्रति शाखा कारोबार का औसत स्तर (कुल जमाराशियों तथा सकल अग्रिमों के अनुसार)

2 वर्ष के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रति कर्मचारी कारोबार का औसत स्तर (कुल जमाराशियों तथा सकल अग्रिमों के अनुसार)

3 वर्ष के दौरान औसत कार्यशील निधियों से अग्रिम तथा निवेश दोनों से कुल आय का प्रतिशत।

4 वर्ष के दोरान औसत कार्यशील निधियों से जमाराशियों, उधार आदि के लिए व्यय किए गए कुल ब्याज का प्रतिशत।

5 वित्तीय प्रतिफल एवं वित्तीय लागत के बीच अंतर।

6 वित्तीय मार्जिन एवं जोखिम, परिचालन एवं अन्य लागत अधिक विविध आय के बीच अंतर।

स्रोत : नाबार्ड।

बॉक्स III.6: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का समामेलन

कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए ऋण के प्रवाह पर बनी सलाहकार समिति (अध्यक्ष : श्री वी.एस.व्यास) ने जून 2004 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन करने की सिफारिश की। इसके अनुपालन में, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मजबूत करने के लिए विद्यमान विधिक ढाँचे के अंतर्गत उपलब्ध अनेक विकल्पों पर विचार करने हेतु रिजर्व बैंक में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर एक आंतरिक कार्यदल बनाया गया।

दल ने, मई 2005 में प्रस्तुत रिपोर्ट में कवर किए गए जिलों की संख्या और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के शाखा संजाल में काफी बड़ा अंतर पाया। जबकि 47 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से प्रत्येक ने केवल एक-एक जिला कवर किया,111 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 2-3 जिले कवर किए, 29 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 4-5 जिले और 9 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 6-9 जिले कवर किए। इसी प्रकार, 72 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 50 शाखाएं, 87 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 51-100 शाखाएं, 21 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 101-150 शाखाएं और 16 की 150 से अधिक शाखाएं थी। इसी प्रकार 6 प्रवर्तक बैंकों की उनके द्वारा प्रवर्तित केवल एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक थीं और 8 प्रवर्तक बैंकों की विभिन्न राज्यों में उनके द्वारा प्रवर्तित 10 से अधिक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक थे। वास्तव में, 2 प्रवर्तक बैंकों के 20 से अधिक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक थे।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की परिचालनात्मक क्षमता को बढ़ाने और इकनॉमीज ऑफ स्केल (लेनदेन की लागत को घटाकर के) का लाभ लेने के लिए, विभिन्न हितधारकारियों के विचारों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलयन/समामेलन का मार्ग सुझाया गया। विलय की गई कंपनियों का परिचालन क्षेत्र व्यापक होगा और विलय की प्रक्रिया कुछ कमजोर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मजबूत करने में मदद करेगी। दो चरण वाले पुनर्गठन का सुझाव दिया गया : (i) किसी राज्य में उसी प्रवर्तक बैंक के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बीच विलय ; (ii) किसी राज्य में विभिन्न बैंकों द्वारा प्रवर्तित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का प्रवर्तक बैंक के साथ विलय संबंधी कोई प्रावधान आरआरबी अधिनियम 1976 में नहीं दिया गया है। इसके अलावा, ऐसा विलयन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को स्थानीय निकाय के रूप में स्थापित करने और मुख्य रूप से कमजोर वर्ग को ऋण प्रदान करने की भावना के विरुद्ध होगा।

भारत सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कमियों को दूर करने और उन्हें सक्षम तथा लाभपूर्ण इकाई बनाने के लिए राज्य स्तर पर प्रवर्तक बैंकवार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के समामेलन की प्रक्रिया चरण-वार शुरू की ।राज्य स्तर पर प्रवर्तक बैंक-वार आरआरबी के समामेलन की प्रक्रिया 12 सितंबर 2005 को जारी अधिसूचना के साथ हुई,जब 9 बैंकों का समामेलन किया गया। 31 मार्च 2005 को, 26 राज्यों के 523 जिलों (2005-06 में 525) में 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्य कर रहे थे जिनकी 14,484 शाखाएं (2005-06 में 14,449)थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का ग्रामीण क्षेत्र में व्यापक शाखा संजाल था जो सभी वाणिज्यिक बैंकागें की ग्रामीण शाखा संजाल का लगभग 45 प्रतिशत था। 18 अक्तूबर 2006 तक, 137 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 43 नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बनाने के लिए समामेलित किया गया, जो 15 राज्यों में 18 बैंकों द्वारा प्रवर्तित किए गए, जिससे पूरे भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल संख्या 196 से घटकर 102 हो गई। चरण I के समामेलन की प्रक्रिया लगभग पूरी होने वाली है।

प्रवर्तक बैंकों को संगठनात्मक स्वरूप, अध्यक्षों की नियुक्ति और स्टाफ की वरिष्ठता के निर्धारण के संबंध में संशोधित दिशानिर्देश जारी किए ताकि वे समामेलन की अवधि के पश्चात उन्हें अपने-अपने संबंधित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में कार्यान्वित करा सकें। समामेलन की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए नाबार्ड पूर्ण दिशा-निर्देश और सहायता प्रदान कर रहा है।

समामेलन के पश्चात् परिचालन क्षेत्र के व्यापक होने के कारण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का आकार और बड़ा हो जाएगा जिससे वे इकनॉमीज ऑफ स्केल का लाभ उठाकर और प्रभावी तरीके से प्रतिस्पर्धी वातावरण में कार्य कर सकेंगे और लेनदेन की लागत कम कर सकेंगे। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या घटाने की प्रक्रिया से प्रवर्तक बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मामलों का और भी अच्छी तरह प्रबंधन कर सकेंगे।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का वित्तीय निष्पादन

3.120 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या मार्च 2005 के अंत के 196 से तुलना करने पर मार्च 2006 के अंत में 133 (समामेलन के कारण) तक घटने के बावजूद, 2005-06 के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का समेकित तुलनपत्र 15.1 प्रतिशत बढ़ा (सारणी III.56)। आस्तियों के पक्ष में, 2005-06 के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के निवल अग्रिम

सारणी III 56: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - समेकित तुलनपत्र

(राशि करोड़ रुपए)

मद	31 मार्च 2005	31 मार्च , 2006 (अ)	प्रतिशत घटबढ़	मद	31 मार्च 2005	31 मार्च 2006 (अ)	प्रतिशत घटबढ़
1	2	3	4	5	6	7	8
देयताएं	**77,867**	**89,645**	**15.1**	**आस्तियां**	**77,867**	**89,645**	**15.1**
शेयर पूंजी	196	196	–				
आरक्षित राशि	3,819	4,271	11.8	उपलब्ध नकदी	966	1,033	6.9
शेयर पूंजी जमा राशि	2,167	2,180	0.6	भा.रि. बैंक के पास शेष	3,026	3519	16.3
जमाराशि	62,143	71,329	14.8	अन्य बैंक शेष	12,230	16,258	32.9
मुद्रा	3,257	3,953	21.4	अन्य निवेश	24,532	24,925	1.6
बचत	30,740	38,233	24.4	ऋण तथा अग्रिम (निवल)	31,803	38,520	21.1
मीयादी	28,146	29,143	3.5	निर्धारित आस्तियां	154	178	15.6
से उधार	5,524	7,303	32.2	अन्य आस्तियां#	5,155	5,214	1.1
नाबार्ड	5,067	6,291	24.2				
स्पॉन्सर बैंक	450	959	113.4				
अन्य	8	53	552.1				
अन्य देयताएं	4,018	4,367	8.7				
ज्ञापन मदें:							
क. ऋण जमा अनुपात	51.2	55.7					
ख.निवेश-जमा अनुपात	39.5	57.7					
ग. (ऋण + निवेश) जमा अनुपात	90.7	113.4					

– : कुछ नहीं। अ : अनंतिम # : संचित हानि सहित ।

स्रोत : नाबार्ड।

21.1 प्रतिशत बढ़े। देयता पक्ष की बड़ी मदों में, वर्ष के दौरान उधार 32.2 प्रतिशत और कुल जमाराशियां 14.8 प्रतिशत बढ़ी ।

3.121 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के समामेलन की दृष्टि से, लाभ कमानेवाले और हानि उठानेवाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या क्रमशः 111 और 22 हो गई, जो मार्च 2006 के अंत में क्रमशः 166 और मार्च 2005 के अंत में 30 थी (सारणी III.57)। 2005-06 के दौरान व्यय की तुलना में आय में तेज गिरावट का परिणाम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के निवल लाभ में 500 करोड़ रुपए की कम वृद्धि के रूप में दिखा, जो 2004-05 के दौरान तुलना करने पर 748 करोड़ रुपए था। वर्ष के दौरान सकल और निवल एनपीए का अनुपात क्रमश: 7.3 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत तेजी से गिरा, जो 80 प्रतिशत तक अच्छी वसूली के कारण संभव हो सका।

3.122 2005-06 के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 32,871 करोड़ रुपए के ऋण जारी किए जिसमें प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का हिस्सा 79.3 प्रतिशत से ऊपर था। मार्च 2006 के अंत में, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बकाया अग्रिम 39,713 करोड़ पर पहुंच गये जिसमें से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का हिस्सा 81.8 प्रतिशत था (सारणी III.58)। कृषि ऋणों का हिस्सा मार्च 2005 के अंत के 50.8 प्रतिशत से मार्च 2006 के अंत में 54.0 प्रतिशत बढ़ा, जबकि इसी अवधि में गैर कृषि ऋण का हिस्सा 49.2 प्रतिशत से 46.0 प्रतिशत गिरा ।

सारणी III.57: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का वित्तीय कार्य-निष्पादन

(राशि करोड़ रुपए)

विवरण	2004-05			2005-06			घटबढ़ स्तंभ (4) पर स्तंभ (7)
	घाटे में चल रहे [30]	लाभ में चल रहे [166]	क्षे.ग्रा.बैं. [196]	घाटे में चल रहे [22]	लाभ में चल रहे [111]	क्षे.ग्रा.बैं. [133]	
1	2	3	4	5	6	7	8
क. आय (i+ii)	**638**	**5,497**	**6,135**	**684**	**4,915**	**5,599**	**-536 (-8.74)**
i. ब्याज आय	597	5,078	5,675	636	4,586	5,222	-453 (-7.98)
ii. अन्य आय	41	419	460	48	329	377	-83
ख. व्यय (i+ii+iii)	**792**	**4,595**	**5,387**	**854**	**4,235**	**5,089**	**-298 (-5.52)**
i. ब्याज व्यय	429	2,731	3,160	438	2,346	2,784	-376 (-11.91)
ii. प्रावधान और प्रासंगिक व्यय	52	208	260	67	211	278	18 (6.75)
iii. परिचालनगत व्यय	311	1,656	1,967	350	1,678	2,028	61 (3.11)
जिसमें से : वेतन बिल	249	1,277	1,526	291	1,290	1,581	55
ग. लाभ							
i. परिचालन लाभ/हानि	-102	1,110	1,008	-104	891	787	-221 (-21.91)
ii. निवल लाभ/हानि	-154	902	748	-170	681	510	-238 (-31.87)
घ. कुल आस्तियां	**9,780**	**68,086**	**77,866**	**11,747**	**77,898**	**88,652**	**10,786 13.85**
ङ. वित्तीय अनुपात #							
i) परिचालन लाभ	-1.04	1.63	1.29	-0.88	1.14	0.89	
ii) निवल लाभ	-1.57	1.32	0.96	-1.45	0.87	0.57	
iii) आय	6.52	8.07	7.88	5.82	6.31	6.32	
iv) ब्याज आय	6.10	7.46	7.29	5.41	5.89	5.89	
v) अन्य आय	0.42	0.62	0.59	0.41	0.42	0.43	
vi) व्यय	8.10	6.75	6.92	7.27	5.44	5.74	
vii) ब्याज व्यय	4.39	4.01	4.06	3.73	3.01	3.14	
viii) परिचालन व्यय	3.18	2.43	2.53	2.98	2.15	2.29	
ix) वेतन बिल	2.55	1.88	1.96	2.47	1.66	1.78	
x) प्रावधान और प्रासंगिक व्यय	0.53	0.31	0.33	0.57	0.27	0.31	
xi) सकल अनर्जक आस्तियां			8.50			7.30	
xii) निवल अनर्जक आस्तिया			5.15			3.96	

: कुल आस्तियों कें अनुपात।

टिप्पणी : 1. कोष्ठक के आंकड़े क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या दर्शाते हैं।
2. स्तंभ 8 में कोष्ठक के आंकड़े वर्ष के दौरान प्रतिशत घट-बढ़ दर्शाते हैं।
3. आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत : नाबार्ड।

सारणी III.58: बकाया अग्रिमों का प्रयोजनवार वर्गीकरण
(मार्चांत)

(राशि करोड़ रुपए)

प्रयोजन	2005	2006P
1	2	3
I. कृषि (i से iii)	**16,710**	**21,394**
	(50.8)	**(54.0)**
i. अल्पावधि ऋण (फसल ऋण)	10,980	14,690
ii. मीयादी ऋण (कृषि तथा संबद्ध गतिविधियों के लिए)	5,730	6,704
iii. परोक्ष अग्रिम	–	–
II. कृषीतर (iv से vii)	**16,161**	**18,319**
	(49.2)	**(46.0)**
iv. ग्रामीण कारीगर, आदि	713	702
v. अन्य उद्योग	580	824
vi. खुदरा व्यापार, आदि	4,364	3,925
vii. अन्य प्रयोजन	10,504	12,868
कुल (I+II)	**32,871**	**39,713**
ज्ञापन मदें :		
a) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	26,077	32,453
b) गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	6,794	7,259
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का हिस्सा (प्रतिशत)	79.3	81.7

अ: अनंतिम

– : कुछ नहीं / नगण्य

टिप्पणी : कोष्ठक के आंकड़े कुल के प्रतिशत हैं।

स्रोत : नाबार्ड।

11. स्थानीय क्षेत्र बैंक

3.123 मार्च 2006 के अंत में चार स्थानीय क्षेत्र बैंक (एलएबी) कार्य कर रहे थे। वे थे : कोस्टल लोकल एरिया बैंक लि., विजयवाड़ा; कैपिटल लोकल एरिया बैंक लि., फगवाड़ा, नवसारी; कृष्ण भीमा समृद्धि लोकल एरिया बैंक लि., महबूबनगर; और सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लि., कोल्हापुर। 2005-06 के दौरान सभी स्थानीय क्षेत्र के बैंकों की आस्तियां, जमाराशियां और सकल अग्रिम उल्लेखनीय रूप से बढ़े (सारणी III.59)।

सारणी III.59: स्थानीय क्षेत्र के बैंकों का प्रोफाइल

(राशि करोड़ रुपए)

बैंक	आस्तियां		जमाराशियां		सकल अग्रिम	
	2005	2006	2005	2006	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7
कैपिटल लोकल एरिया बैंक लि.	179	252	151	215	90	135
कोस्टल लोकल एरिया बैंक लि.	45	64	36	50	20	30
कृष्णा भीमा समृद्धि लोकल बैंक लि.	17	29	8	13	12	19
सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लि.	12	19	5	12	8	13

स्रोत : अप्रत्यक्ष विवरणी पर आधारित।

3.124 2005-06 के दौरान एलएबी की आय में तेज वृद्धि हुई। आय में अधिक वृद्धि मुख्य रूप से ब्याज आय के कारण थी। व्यय के पक्ष में, वर्ष के दौरान ब्याज व्यय और परिचालन व्यय में काफी वृद्धि हुई। आय में बढ़ोत्तरी व्यय से अधिक थी जिसका परिणाम पिछले वर्ष के 0.9 प्रतिशत की तुलना में 2.8 प्रतिशत के अधिक लाभ के रूप में हुआ। (सारणी III.60)।

सारणी III.60: स्थानीय क्षेत्र के बैंकों का वित्तीय कार्य निष्पादन
(मार्च के अंत के अनुसार)

(राशि करोड़ रुपए)

संकेतक	2004-05	2005-06	घट-बढ़	
			राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5
क. आय (i+ii)	**21.3**	**30.0**	**8.7**	**41.1**
i) ब्याज आय	17.3	25.5	8.2	47.4
ii) अन्य आय	4.0	4.5	0.5	13.6
ख. व्यय (i+ii+iii)	**20.4**	**27.2**	**6.8**	**33.6**
i) ब्याज व्यय	8.7	12.0	3.3	38.0
ii) प्रावधान और प्रासंगिक व्यय	2.5	2.6	0.1	5.6
iii) परिचालनगत व्यय	9.2	12.6	3.4	37.0
जिनमें से :				
वेतन बिल	3.1	4.5	1.4	44.5
ग. लाभ				
i) **परिचालनगत लाभ / हानि**	3.4	5.4	2.0	59.9
ii) **निवल लाभ / हानि**	0.9	2.8	1.9	210.8
घ. स्प्रेड (निवल ब्याज आय)	**8.6**	**13.5**	**4.9**	**56.9**

स्रोत :अप्रत्यक्ष विवरणियों पर आधारित ।